मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- अरहर की आसमान छूती कीमतों पर अरबों रूपए का खेल हो गया। 3
- बिहार में नहीं गलेगी मोदी जी का दाल 4
- इन्सान ने ही भगवान का निर्माण किया है - इसके सबूत हैं।
- अगर पहले मुआवजा दे दें तो मरने की जरूरत नही 5
- विज के दावों का हर रोज़ फूटता भंडा बीके अस्पताल बना लूट का अड्डा 8

वर्ष 28 अंक 24 फरीदाबाद, रविवार, 1-15 नवम्बर 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

लोमहर्षक सुनपेड़ अग्निकांड पर कोई सच नहीं बोलना चाहता !

बीते पखवाड़े 19 अक्टूबर को बल्लबगढ से सटे गांव सुनपेड़ के एक दलित घर में हुए अग्निकांड में दो शिशु जिंदा जल मरे तथा उनकी मां रेखा गंभीर हालत में अभी तक दिल्ली के सफ़दरजंग अस्पताल में ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है। बच्चों के पिता जितेंद्र के दोनों हाथों की हथेलियां व अंगुलियां मामूली जली थीं, जो मरहम पट्टी के बाद ठीक भी हो गयीं।

फ़रीदाबाद (म.मो.)

झोलाछाप डॉक्टर जितेन्द्र ने अग्निकांड में गांव के उन 11 ठाकुरों को नामजद कर दिया। जिनके साथ उसके परिवार की एक वर्ष से मुकदमेबाज़ी चल रही थी। चमार जाति से होने के कारण जितेन्द्र को दलित तथा आरोपी राजपूत जाति से होने के कारण दबंग बताये गये। जबकि आर्थिक स्थिति दोनों की लगभग एक जैसी ही है बल्कि जितेन्द्र की स्थिति कुछ ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस देश का माहौल, राजनीतिज्ञों ने कुछ ऐसा बिगाड़ दिया है कि जब कहीं दलित का नाम जुड़ जाय तो फ़िर सबको राजनीति ही सूझती है। सारी सरकार, पक्ष-विपक्ष, अफ़सर व मीडिया एक अंधी दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में पिल पड़ते हैं। कोई भी सच्चाई एवं वास्तविकता को जानने का इच्छुक नहीं होता और न उसे प्रकट करने की हिम्मत जुटा पाता है।

अग्निकांड का समय प्रात: 3 बजे का था। जितेन्द्र के घर की बगल में (करीब 30-40 मीटर पर) पूरे गाजे-बाजे के साथ धार्मिक कीर्तन चल रहा था। गांव के अधिकांश लोग उसमें मौजूद थे। ठंड बढने के कारण कुछ लोग बीच में उठ-उठ कर अपने घरों से चादर भी ओढ कर आ रहे थे। वारदात से कुछ ही देर पहले जितेन्द्र की मां भी अपने घर से चादर ओढ कर आई थी। जाहिर है उस वक्त जितेन्द्र व रेखा भी जागे हुए होंगे।

जितेन्द्र ने अपने बयान में पुलिस को कहा कि कीर्तन के शोर से वह सो नहीं पा रहा था। इसी बीच उसे पेट्रोल की गंध आई जो उसके कमरे की खिड़की से भीतर फ़ेंका गया था; वह कुछ संभल पाता इतने में किसी ने बाहर से जलती हुई तिल्ली फ़ेंक दी। वह

क्या असल हत्यारे को सजा मिल पायेगी ?

आग बुझाने व बच्चों को बचाने में लग गया और इसी बीच उसने अंधेरे में 11 आदमियों को वारदात करते उसी खिड़की में से देख भी लिया। उसने घर से बाहर निकलने का प्रयास किया तो दरवाजा बाहर से बंद पाया।

मौके की सच्चाई यह है कि जितेन्द्र की उक्त खिड़की तक पहुंचने के लिये 6 फ़ीट से ऊंची दीवार फ़ांदनी पड़ती है, क्योंकि चारदीवारी में लगा गेट सहायता करने आये लोगों ने अन्दर से बन्द पाया था। इसे जितेन्द्र अथवा रेखा ने अपनी मां जो कुछ देर पहले चादर ओढ कर गयी थी, के जाने के बाद बंद किया होगा। जितेन्द्र द्वारा बताये गये 11 आरोपियों में से एक बलमत की आयु 70 वर्ष से ऊपर है जो दीवार फ़ांद ही नहीं सकता और फ़िर ऐसे काम के लिये 11 आदमियों को दीवार फ़ांदने की जरूरत ही क्या थी। यदि उन्हें यही काम करना था तो एक या दो ही काफ़ी रहते।

उक्त 11 को आरोपित बनाने का रहस्य यह है कि ठीक एक वर्ष पूर्व यानी अक्टूबर 2014 में जितेन्द्र के पिता एवं अन्य कुल 11 दलित जाति के लोगों ने राजपूतों के 3 लोगों की दिन दहाड़े हुए झगड़े में हत्या कर दी थी। उस तिहरे हत्याकांड में जितेन्द्र के पिता सहित 11 को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया था। इनमें 2 महिलायें भी थीं जिनकी

शेष पेज दो पर

सीबीआई बनाम महापंचायत

अपनी फ़ंसी जान छुड़ाने के लिये खट्टर सरकार ने सुनपेड़ का 'जंजाल' तुर्त-फ़ुर्त सीबीआई के हवाले कर दिया है। कोई पूछे कि इतने सीधे व स्पष्ट मामले में राज्य की पुलिस निष्पक्ष कार्यवाही क्यों नहीं कर सकती ?

दूसरी तरफ़ शासन व प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी से भागता देख कर आरोपी पक्ष ने महापंचायत बुला ली, जिससे जातीय तनाव में और वृद्धि ही हुई है। क्या इसके लिये खट्टर सरकार की लीपापोती को दोष नहीं दिया जाना चाहिये ? सीबीआई बनाम महापंचायत का यह खेल विशुद्ध जातिवादी राजनीति का खेल ही है। राजनेता तो इस खेल को खेलने में माहिर हैं पर जनता के सम्बन्धित वर्ग बिना वजह पिसते रहेंगे।

महानालायक को बनाया एसएचओ सदर

तनावग्रस्त गांव सुनपेड़ थाना सदर बल्लबगढ के अन्तर्गत आता है। अग्निकांड के बाद 7 पुलिसकर्मियों को निलम्बित करने के साथ-साथ इस थाने के एसएचओ का भी तबादला करके लाइन में भेज दिया था। उनके स्थान पर लगाया गया है अनिल कटारिया को।

सुधी पाठक जान लें कि यह वही अनिल कटरिया है जो सन् 2012-13 में एसएचओ एनआईटी फ़रीदाबाद में तैनात था। इस दौरान सेक्टर 21 ए के मकान नम्बर 631 में एक नौकर की हत्या हो गयी थी। इस नालायक बेरहम एवं भ्रष्टाचारी ने दो ग़रीब रंगाई-पुताई करने वाले मज़दूरो को पकड़ा, पीट-पीट कर उनसे हत्या का गुनाह कबूल करवा लिया। उन्हें सज़ा करवाने के लिये झूठे साक्ष्य तैयार करके सेशन कोर्ट में पेश करके उन्हें सज़ा के करीब तक पहुंचा दिया था।

दूसरी ओर सीआईए के एक एएसआई दिलावर सिंह ने चोरी की तफ़्तीश के दौरान उक्त हत्याकांड के असली दोषियों को खोज़ निकाला था। तत्कालीन सीपी (पुलिस आयुक्त) शत्रुजीत कपूर सहित तमाम पुलिस अधिकारियों के नोटिस में केस को लाया गया। लेकिन सीपी कपूर का कमाऊ पूत होने के नाते उन्होंने इस नालायक बेरहम एसएचओ के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की और न ही निर्दोष हत्यारोपियों को जेल से छुड़वाने की कोई कार्यवाही की। उधर इस नालायक एसएचओ ने अधिक होशियारी दिखाते हुए एएसआई दिलावर की जिमनी के वे दो पेज ही मिसल से गायब कर दिये जिनमें चोरों ने हत्या करना स्वीकारा था।

इस प्रकार एसएचओ ने पहले अपराध को छुपाने के लिये दूसरा अपराध भी कर दिया। दोनों ही गंभीर एवं जेल जाने वाले अपराध हैं। परन्तु जिसके सिर पर शत्रुजीत कपूर, जो कि आज बतौर सीआईडी प्रमुख खट्टर के मूंछ के बाल बने बैठे हैं, का हाथ हो उसे जेल कौन भेजे? हां एएसआई दिलावर को जरूर सज़ा के तौर पर 2 वर्ष की वेतनवृद्धि काटने का नोटिस दे दिया गया है।

इस सारे मामले का रहस्योद्घाटन 'मज़दूर मोर्चा' द्वारा 1-15 जनवरी 2014 के अंक में कर दिये जाने के बाद तत्कालीन सैशन जज ने दोनों निर्दोषों को बरी करते हुए पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश जारी किये थे। अब देखना है कि यह नालायक एसएचओ अपनी इस तेनाती के दौरान और क्या-क्या करतब दिखाता है।

ख़बर दार

अबकि बार मुँहफटों की सरकार

कोई कुत्ता बोला रहा है, कोई पिल्ला कह रहा है, कोई आंतकवादी तो कोई देशद्रोही कह रहा है, कोई रामजादे-हरामजादे का वर्गीकरण पेश कर रहा है, कोई पाकिस्तान भेज रहा है तो कोई अरब सागर में डुबो रहा है, कोई दस बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहा है, कोई महिलाओं की आजादी को नंगापन कह रहा है, कोई कह रहा है रेप इंडिया में होते हैं भारत में नहीं, कोई मटन और बीफ की तुलना पत्नी और बहन से कर रहा है..... आप माने या न माने, यही है अच्छे दिन। इसी पृष्ठभूमि में वीके सिंह से एक काल्पनिक साक्षात्कार।

दलित बच्चों की हत्या पर बोले वीके सिंह : कोई कुत्ते को पत्थर मार दे, तो क्या सरकार जिम्मेवार है

म.मो.-जनरल साहब आप जब फ़ौज में थे तब भी इसी तरह के अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते थे ?

जनरल-क्या करूं भाई फ़ौजी आदमी ठहरा। मन की बात छुपाये नहीं छुपती। बस जुबान पर आ ही जाती है।

म.मो.-फ़ौज में तो आप दूसरे जनरलों को बेइमान और देशद्रोही बताया करते थे। क्या वह सब ठीक था ?

जनरल-वे भी मुझे झूठा जन्म प्रमाणपत्र देने वाला और कुर्सी लोलूप बताया करते थे। हमारे देश की तो यही संस्कृति है कि जो तुम्हे झूठा बताये वही बेईमान और जो लालची बताये वही देशद्रोही। देखते नहीं कि मेरी पार्टी भाजपा भी इसी सिद्धान्त पर चल रही है।

म.मो.-लेकिन एक इतनी बड़ी इन्सानी ट्रेजडी जो गांव सुनपेड में हुई, उसकी तुलना आपने कुत्ते को पत्थर मारने से कर दी ? क्या यह गलत नही हुआ ?

जनरल-हां मुझसे यह ग़लती जरूर हुई कि मैंने दोनों बातें मिला दीं जबकि कुत्तों के बारे में तो मुझे अलग से बोलना चाहिये था। अरे फ़ौज की 40 साल की लम्बी नौकरी ने मुझे कुत्तों का एक्सपर्ट भी तो बना दिया है।

म.मो.-आपकी टिप्पणी को जाति विशेष को अपमानित करने वाली माना जा रहा है ?

जनरल-मुझे पता है। यहां तक कि विरोधी पार्टी वाले तो मेरे खिलाफ़ मुकदमे दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। पर किसी दलित की यह मजाल नहीं कि मेरी बात को काट सके। हम भी हरियाणा के ठाकुर हैं। अगर पहले कुछ कह भी दिया तो अब माफ़ी भी मांग ली है।

म.मो.-इस तरह तो आप जैसे लोग गाली देते रहेंगे और माफ़ी मांगते रहेंगे, तो क्या आपको माफ़ कर दिया जायेगा ? यह बहन मायावती का कहना है।

जनरल-**ब**हन मायावती जी को बोलने दो! क्या उन्हें सीबीआई से माफ़ी नहीं चाहिये ? देखना, वे चुप्पी लगा जायेंगी। आखिर उनके सिर पर लटकती सीबीआई की तलवार हमारी सरकार के हाथों में ही तो है।

म.मो.-क्या आपको कुत्ते की उपमा देने का दिल से अफ़सोस है ?

जनरल-राजनीति में दिल का क्या काम ? मुंह से जो बोलना था बोल दिया। मुंह से ही खेद प्रकट कर दिया। मैंने यह कलाकारी राजनीति के धुरंधरों से ही तो सीखी है। वरना आप भी जानते हो कि मैं इस क्षेत्र में नया खिलाड़ी हूं। हम कुर्सी पाने के लिये कुछ भी बोल देते हैं और बचाने के लिये कभी भी माफ़ी मांग लेते हैं।

मोदी का गिरता भाव: नीतिश लालू की बढती नाव

बिहार चुनाव में मोदी ने अपनी जान भी दांव पर लगा दी है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण समीक्षा वाले बयान ने बिहार के मतदाताओं में भाजपा को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है। रही सही कसर वित्त मन्त्री अरूण जेटली द्वारा दाल के आसमान छूते भाव को वैश्वीकरण का प्रभाव बता कर उचित ठहराने ने पूरी कर दी है। दूसरे शब्दों में रोज़गार और मंहगाई को लेकर मोदी सरकार की विफ़लता का डंका बिहार चुनाव में सुनाई दे रहा है।

भाजपा को उम्मीद थी कि लालू के 'जंगलराज' को वे नीतीश को भोंथरा करने में इस्तेमाल कर पायेंगे। पर जंगलराज का हव्वा चला हुआ कारतूस सिद्ध हुआ है बिहार की जनता पहले ही लालू को उनके किये की भरपूर सज़ा दे चुकी है, और अब उसे किसी भी भाजपाई नेता या पासवान मांझी जेसे उनके सहयोगियों के मुकाबले नीतीश के 'सुशासन' पर ज़्यादा भरोसा है।

कायदे से चुनावी गणित को 10 वर्ष से बिहार में शासन कर रहे नीतीश के विपरीत 'एन्टी इन्कम्बेंसी' के समीकरण से चलना चाहिये था। पर केन्द्र में मोदी का अपना डेढ वर्ष का कुशासन इस समीकरण को नीतीश-लालू के पक्ष में कर गया है। भूलना नहीं चाहिये कि बिहार के लोग आज भी करीब 90 प्रतिशत कृषि पर निर्भर हैं। वे भला मोदी के कार्पोरेट रूझान वाले भूमि अधिग्रहण बिल की किसान विरोधी मंशा को कैसे भूल सकते हैं ? लिहाज़ा, बेशक बिहार में बिका हुआ मीडिया जातिवाद, गाय, जंगलराज, तंत्र-मंत्र इत्यादि को मुख्य चुनावी मुद्दा बना रहा हो, लेकिन मतदाता के लिये आरक्षण, मंहगाई, रोज़गार और विकास ही अहमियत रखते हैं। इस पैमाने पर मोदी का भाव लगातार गिरता जा रहा है। जाहिर है, ऐसे में एकमात्र विजयी विकल्प नीतीश-लालू ही होने जा रहे हैं।